



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 979/2025

रियाजउद्दीन

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अजय शंकर. त्रिवेणी शंकर
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण अग्रवाल, संजय कुमार सिंह,
सुशील कुमार पांडेय. वेद प्रकाश मिश्रा

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र,

1. यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा एस एच5ए पर स्थित रॉबर्ट्सगंज फ्लाईओवर पर स्ट्रीटलाइट लगाने के मामले में 9.32 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी की जांच की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिका में आरोप लगाया गया था कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ('पीवीवीएनएल') के कार्यकारी अभियंता द्वारा दिनांक 30.10.2023 के एक पत्र (अनुलग्नक-1) के माध्यम से यह दर्शाया गया था कि रॉबर्ट्सगंज फ्लाईओवर पर स्ट्रीटलाइट लगाने के लिए 9.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि वास्तव में स्ट्रीटलाइट उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगाई गई थीं और यह कार्य 1,58,52,175 रुपये की लागत से किया गया था, जैसा कि दिनांक 30.04.2024 के पत्र (अनुलग्नक-9) से स्पष्ट है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि स्ट्रीटलाइट लगाने के नाम पर 9.32 करोड़ रुपये का गबन किया गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 और 5, अर्थात् प्रबंध निदेशक, पीवीवीएनएल और कार्यकारी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, पीवीवीएनआई को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. एक प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें यह बताया गया कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की कार्यकारी परिषद ने 15.04.2018 को हुई अपनी बैठक में रिलायंस पेट्रोल पंप से लोरी अस्पताल तक और टोल प्लाजा से सौन तक एलईडी स्ट्रीटलाइट लगाने के कार्य को मंजूरी दी थी। इको प्वाइंट के लिए 9,20,45,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके आधार पर ग्रिड पावर सिस्टम और अधीक्षण अभियंता, पीवीवीएनएल के बीच स्वीकृत कार्य के लिए एक समझौता किया गया था।

5. जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की कार्यकारी परिषद की दिनांक 17.06.2019 को हुई बैठक में, विंध्याचल क्षेत्र के आयुक्त द्वारा पूर्व में स्वीकृत कार्यों के संबंध में आपत्ति उठाई गई, जिसके आधार पर कार्य के प्रस्ताव में परिवर्तन किया गया और इसे 11.07.2019 को अनुमोदित किया गया।

6. यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को आरटीआई आवेदन का गलत जवाब दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि स्ट्रीटलाइट लगाने के लिए 9.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि वास्तव में नव स्वीकृत छह कार्यों के लिए 9,58,16,000 रुपये खर्च किए गए थे। यह भी बताया गया कि वास्तव में विचाराधीन कार्य फ्लाईओवर पर नहीं, बल्कि रॉबर्ट्सगंज फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सहित छह अलग-अलग स्थानों पर किया गया था, इसलिए लगाए गए आरोप निराधार हैं।

7. याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सोनभद्र नगर पालिका परिषद से प्राप्त जवाब के साथ एक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया, जिसमें रॉबर्ट्सगंज फ्लाईओवर पुल के नीचे की स्ट्रीटलाइटों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि फ्लाईओवर के निर्माण से पहले विभाग ने स्ट्रीटलाइटें लगाई थीं। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि फिर से एक गलत दावा किया गया है, वास्तव में, राशि का गबन किया गया है।

8. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है जो याचिका, प्रतिवाद हलफनामे और प्रत्युत्तर हलफनामे में उठाए गए तर्क के अनुरूप हैं।

9. यह याचिका पीवीवीएनएल द्वारा रॉबर्ट्सगंज फ्लाईओवर पर स्ट्रीटलाइट लगाने के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर दायर की गई थी। चूंकि स्ट्रीटलाइट उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगाई गई थीं, पीवीवीएनएल ने अपने प्रतिवाद हलफनामे में रॉबर्ट्सगंज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फ्लाईओवर के अंतर्गत आने वाले छह अलग-अलग खंडों को एलईडी लाइटों से रोशन करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की। यह याचिका नगर पालिका परिषद द्वारा आरटीआई के जवाब में स्ट्रीटलाइट लगाने के संबंध में दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर चुनौती दी गई है। फ्लाईओवर के निर्माण से पहले उसके नीचे लगी स्ट्रीटलाइटें।

10. यह स्वीकार किया जाता है कि फ्लाईओवर का निर्माण वर्ष 2018 में पूरा हो गया था, लेकिन इसके निर्माण में कितना समय लगा, यह ज्ञात नहीं है। हालांकि, चूंकि यह संकेत मिलता है कि नगर पालिका परिषद द्वारा फ्लाईओवर के निर्माण से पहले ही स्ट्रीटलाइटें लगाई गई थीं, इसलिए पीवीवीएनएल द्वारा ओवरब्रिज के नीचे एलईडी लाइटें लगाने का दावा ओवरब्रिज के निर्माण के कम से कम 4 से 5 साल बाद शुरू हुआ होगा, और चूंकि एलईडी लाइटों के अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता पीवीवीएनएल अधिकारियों पर किसी प्रकार से गबन का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जो अस्वीकार्य है।

11. परिणामस्वरूप, रिट याचिका में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

फरवरी 12, 2026

एएचए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”